(b) In Annual Plan 1995-96, an outlay of Rs. 721.43 crores has been provided for modernisation and expension of Major Ports in the country. The Port-wise allocation of funds is as under:

	(Rs. in crores)
Calcutta/Haldia	60.32
Bombay	143.61
J.L. Nehru	55.24
Madras	92.59
Cochin	50.00
Vizag.	53.00
Kandla	30.92
Mormugao	27.28
Paradip	77.93
New Mangalore	107.44
Tuticorin	23.10

During the current financial year 1995-96, an outlay of Rs. 198.85 crores has been provided for Major Ports in Maharashtra (Rs. 143.61 crores for Bombay and Rs. 55.24 crores for J.L. Nehru Port). The major projects under implementation at Major Ports in Maharashtra are as given below:

BOMBAY

(i) Replacement of submarine pipelines connection the Marine Oil Terminal at Jawahar Dweep and Pir Pau manifold; and

(ii) Consturction of an oil berth in replacement of an oil berth at Pir Pau.

J.L. NEHRU

Construction of approach/Bridge to service berths.

(c) The Ports do not pay demurrages on ships. Such demurrage, if any, is borne by the concerned Charterers/ Shipping agents.

(d) Various steps have been taken to improve the performance profile of Major Ports in the country, keeping in view the demands, Provisions of required infrastructure for handling the traffic at various Major Ports, relaxation of Cobotage Law, Rationalisation of manning scales and Privatisation in the areas where are constraints.

नशीले पदार्थों का अवैध धन्धा करने वाले लोगों को दंड दिया जाना

1095. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा नशीली पदार्थों का अवैध धन्धा करने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक स्थानों पर नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार पुलिस की मिली भगत से किया जा रहा है;

(ग) कितने और कौन-कौन से देशों में नशीले पदार्थों का अवैध धन्धा करने वालों को मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान है; और

(घ) क्या भारत सरकार भी इस अपराध के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करने पर विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) वर्ष 1992, 1993, 1994 और 1995 (30.6.95 तक) के दौरान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1992	926
1993	801
1994	757
1995 (30.6.95 तक)	404

(ख) ऐसी कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के

पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी नहीं श्रीमान्। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 31-क के अधीन पहले ही एक उपबंध है जिसमें दूसरी बार दोष-सिद्ध हो जाने पर कुछ अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है।

दिल्ली पुलिस में होम गार्डों की नई नियुक्ति पर प्रतिबंध

1096. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के होम गार्ड विभाग में भारी वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत को ध्यान में रखते हुए होम गार्डों की नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले अनेक वर्षों से हो रही इन वित्तीय अनियमितताओं की जांच किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस जांच का कार्यभार किस स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है;

(घ) क्या जांच-कार्य प्रारंभ कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, क्या जांच के दौरान कतिपय और तथ्य भी प्रकाश में आए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस जांच कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दिल्ली सरकार ने होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय के वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लेखों की विशेष परीक्षा करने के आदेश दिए हैं।

(ग) इस विशेष लेखा परीक्षा दल में एक निरीक्षक लेखा परीक्षा अधिकारी (वरिष्ठ लेखा अधिकारी) है, जिनकी सहायता के लिए तीन कनिष्ठ लेखा अधिकारी हैं।

(घ) से (च) इस विशेष लेखा परीक्षा दल ने 6.7.95 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और पूरी तस्वीर इसकी रिपोर्ट पूरी होने पर उपलब्ध होने की संभावना है।

Plans to set up Oranges Processing Industries

1097. SHRI JAGIR SINGH DARD:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) what are Government's plans for encouraging the setting up of processing industries in the area of oranges;

(b) what are the prospects of this industry; and

(c) how does our industry compare with that of the orange processing industries in developing countries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) While the Ministry of Food Processing Industries is implementing various plan schemes for the setting up/development of fruit and vegetable processing industries, there is no scheme exclusively for oranges.

(b) The growth rate of Orange processing Industry has been negligible since last many years.

(c) Indian Orange processing industry does not compare favourably against the developing countries like Brazil.

Water Purification Compaign for Godavari River

1098. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what steps are proposed to develop a water purification compaign for river Godavari on the same lines as the Ganga Project;

(b) whether any survey has been done of the Godavari river from Polavaram to Rajahmundry; and

(c) if so, the details thereof?